EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By: - Aarav Anand
Date: 10 Dec 2025
Source:- जनसत्ता

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शुल्क लगाने की धमकी देते हुए कहा

भारत को अमेरिकी बाजार में सस्ते दाम पर चावल नहीं बेचना चाहिए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 दिसंबर।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल 'डंप' करना (सस्ते दामों पर बेचना) नहीं चाहिए और वे इस मामले से 'निपट लेंगे'। ट्रंप ने चेतावनी दी कि शुल्क (टैरिफ) लगाकर इस समस्या का आसानी से हल निकल जाएगा।

ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'वाइट हाउस' में खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों खासकर वित्त मंत्री स्काट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस के साथ एक गोलमेज बैठक की। उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डालर की संघीय सहायता की घोषणा की।

लुइसियाना में अपने परिवार के कृषि कारोबार 'केनेडी राइस मिल' का संचालन करने वाली मेरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि देश के दक्षिणी हिस्से में चावल उत्पादक 'संघर्ष कर रहे हैं' और अन्य देश अमेरिकी बाजार में चावल 'डंप' कर रहे हैं यानी कि बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों वित्त मंत्री स्काट बैसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस के साथ एक गोलमेज बैठक की।

जब ट्रंप ने पूछा कि कौन से देश अमेरिका में चावल सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तो राष्ट्रपति के बगल में बैठीं केनेडी ने जवाब दिया कि भारत और थाईलैंड यहां तक कि चीन भी प्यूर्टो रिको में चावल सस्ते दामों पर बेच रहा है। प्यूर्टो रिको कभी अमेरिकी चावल का सबसे बड़ा बाजार होता था। हमने कई वर्षों से प्यूर्टो रिको में चावल नहीं भेजे हैं। ट्रंप ने फिर बेसेंट की ओर देखते हुए कहा कि भारत, मुझे भारत के बारे में बताइए। भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें शुल्क देना होगा। क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है? इस पर बेसेंट ने कहा कि नहीं, हम अभी उनके साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।

केनेडी ने ट्रंप को यह भी बताया कि भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) में एक मामला चल रहा है।

'इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन' के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 28 फीसद हिस्सेदारी रखता है।

व्यापार वार्ता आज से

भारत–अमेरिका 10 व 11 दिसंबर को फिर से व्यापार वार्ता करेंगे। अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के साथ चर्चा करेगा। वार्ता के लिए अमेरिका के मुख्य वार्ताकार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच, भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन के साथ बातचीत करेंगे।

असुरक्षित सड़कों पर हादसों का सफर

देश में सड़क पर सुरक्षा का मसला अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हों, एक्सप्रेस-वे हों या फिर संपर्क मार्ग, हर जगह रोजाना बड़ी संख्या में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए कोई भी उपाय अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ है।

अखिलेश आर्येंदु

देश में सड़कों पर सुरक्षा का मसला अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हों, एक्सप्रेस-वे हों या फिर संपर्क मार्ग, हर जगह रोजाना बड़ी संख्या में लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यह आशंका हमेशा बनी रहती है कि पता नहीं कब, किस मार्ग पर किसके साथ हादसा हो जाए। सवाल है कि तमाम सड़कों पर वाहनों में या पैदल यात्रा करना अब इतना जोखिम भरा और खतरनाक क्यों होता जा रहा है? बड़े वाहन हो या फिर दो पहिया, किसी पर भी यात्रा करना अब सुरक्षित नहीं रह गया है? सबसे ज्यादा खतरा पैदल यात्रियों को सताने लगा है। सड़क की इस हकीकत से सरकार और प्रशासनिक अमला सभी भली-भांति वाकिफ हैं। मगर हादसों को रोकने के लिए कोई भी उपाय अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ है।

भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023 में देशभर में 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिसमें से 1.72 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत हो गई। यह तब है, जब देश में सड़क तंत्र का महज दो फीसद हिस्सा-राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो 30-35 फीसद मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि देश भर में सभी तरह की सड़क दुर्घटनाओं में होने मौतों में सबसे ज्यादा भूमिका राष्ट्रीय राजमार्गों की है। चिंता की बात यह है कि तमाम सुरक्षात्मक नियमों, कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद राजमार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी आने के बजाय इनकी संख्या लगातार बढ़ रही हैं। जिन कारणों से सड़क हादसों में तेजी आई है, उनमें खराब सड़क अभियांत्रिकी भी है, जिसमें अंधे मोड़, तिरछे-आड़े मोड़ और जरूरी सुरक्षा संकेतों की कमी शामिल है। इसके अलावा सीमा से अधिक गति, चालकों की थकान और ध्यान विचलन भी एक बड़ी वजह है। कमजोर प्रवर्तन भी राजमार्ग पर हादसों का एक कारण है, जिसमें यातायात प्रबंधन की कमी और सीमित गति कैमरों के कारण नियमों का पालन न हो पाना है। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी, पर्याप्त रोशनी का अभाव, कोहरा, लापरवाही से वाहन चलाना और अचानक ब्रेक फेल हो जाना भी हादसों की वजह बन रहा है।

सड़क सुरक्षा के लिए महज अवसंरचना का विकास ही जरूरी नहीं है, बल्कि वक्त के अनुसार सुरक्षा नियमों में बदलाव और व्यापक जनजागरूकता भी आवश्यक है। पिछले दस वर्षों में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क हादसों को कम करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए हैं, लेकिन उससे हादसों में कमी नहीं आई। इन कदमों के तहत सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए केंद्र से राज्यों को निर्देश तथा सड़कों के डिजाइन, संकेतकों और लेन में सुधार के अलावा 'ब्लैक स्पाट' की पहचान एवं सुधार कार्य में तेजी लाना जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने उन्नति पूर्ण चालक सचेत यांत्रिकी यानी एडीएएस को सभी ट्रक और बसों में अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसी तरह अक्तूबर, 2027 तक वाहनों के नए माडल में स्वचालित आपात ब्रेक प्रणाली, 'ड्राइवर ड्रोजिनेस अलर्ट' और 'लेन डिपार्चर वार्निंग' प्रणाली

लगाना जरूरी होगा। वर्ष 2028 से सभी पुराने माडल में भी ये व्यवस्थाएं करनी होंगी। मगर, राजमार्गों पर बढ़ती वाहनों की संख्या की वजह से ये कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं।

जाहिर है कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महज नीतिगत सुधार के अलावा व्यावहारिक रूप से हादसों को रोकने के लिए और भी ज्यादा सुधार करने होंगे। जब तक नीति, कानून और कार्यान्वयन पर बराबर गौर नहीं किया जाएगा, तब तक सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित और भयरहित नहीं बन पाएंगी। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने एक मिसाल पेश की है। इसके तहत विशेष राजमार्ग पुलिस बल का गठन किया गया है। इस बल में दो हजार से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, जो राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर निरंतर गश्त और निगरानी करते हैं। महाराष्ट्र का यह माडल दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। अगर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करे, तो सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरे राज्यों में यह जिम्मेदारी राज्य पुलिस और यातायात पुलिस इकाइयां बखूबी निभा सकती हैं। आजादी के बाद से तमाम सुरक्षा जरूरतों के लिए पुलिस या सुरक्षा बलों का गठन किया गया, लेकिन यातायात सुरक्षा बल का गठन केंद्रीय स्तर पर नहीं हो सका है। सवाल है कि जब सरकार सड़क सुरक्षा के लिए बजट में निर्धारित राशि भी खर्च न कर पा रही हो, तो सुधार की उम्मीद कैसे बने?

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महज नीतिगत सुधार के अलावा व्यावहारिक रूप से हादसों को रोकने के लिए और भी ज्यादा सुधार करने होंगे। जब तक नीति, कानून और कार्यान्वयन पर बराबर गौर नहीं किया जाएगा, तब तक सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित और भयरहित नहीं बन पाएंगी। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने एक मिसाल पेश की है। इसके तहत विशेष राजमार्ग पुलिस बल का गठन किया गया है। इस बल में दो हजार से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, जो राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर निरंतर गश्त और निगरानी करते हैं। महाराष्ट्र का यह माडल दूसरे राज्यों भी अपनाया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'गति प्रबंधन दिशा-निर्देश' जितनी जल्दी हो सके, लागू किए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। सड़क हादसों में आ रही तेजी को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके तहत तत्काल कुछ विशेष तरह के कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन जितनी जल्दी हो सके, सरकार को करना चाहिए। जिससे सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी तरह की नीतिगत, तकनीकी और संस्थागत एजंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा, देश के लिए राष्ट्रीय गति प्रबंधन दिशा-निर्देश तैयार करने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत गति निगरानी, कैमरा-आधारित प्रवर्तन और स्वचालित दंड प्रणाली को बेहतर बनाए जा सके। तीसरा, राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य परिवहन विभाग और राज्य सरकारों के बीच नियमित संयुक्त समीक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि सड़क सुरक्षा योजनाओं, 'ब्लैक स्पाट' सुधार कार्यों और प्रवर्तन गतिविधियों की प्रगति पर नजर रखी जा सके। इससे देश भर में सड़क सुरक्षा की बेहतर निगरानी हो सकेगी और हादसों में हो रही वृद्धि को कम करने में भी मदद मिलेगी।

सड़क सुरक्षा वास्तव में जीवन सुरक्षा, परिवार सुरक्षा, समाज सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसलिए इसे जितनी दृढ़ता, गंभीरता और प्राथमिकता दी जाए, उतना बेहतर होगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा-सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके तहत वाहन चलाने का बेहतर प्रशिक्षण हासिल करना, नशे में वाहन न चलाना तथा यातायात नियमों और कानूनों का पूरी तरह पालन करना होगा। किसी वाहन से आगे निकलने की होड़ वाली प्रवृत्ति को त्यागना होगा, जो न केवल अपनी जान को जोखिम में डालती है, बल्कि दूसरे की जिंदगी से भी खिलवाड़ करती है। अपनी सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही दूसरे की सुरक्षा भी है। लापरवाही या सड़क नियमों को तोड़कर आगे बढ़ना हादसे को निमंत्रण देना है। दो पहिया वाहनों पर सवार लोगों के हर हाल में हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट बांधने तथा गति सीमा का पालन करने से हादसों की भयावहता को कम किया जा सकता है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ सरकारी स्तर पर प्रयासों से ही देश में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह सब शासन, प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है।

संविधान की पहली प्रति आज भी मूल स्वरूप में मौजूद

पंकज रोहिला

देश के संविधान की मूल प्रति नाइट्रोजन गैस कक्ष की बदौलत आज भी एकदम पुराने स्वरूप में उपलब्ध है। यह गैस कक्ष अमेरिका की तर्ज पर तैयार किया गया है और हर साल इस कक्ष को खाली किया जाता है। संविधान की मूल कापी को अंग्रेजी-हिंदी में लिखा गया है और यह कुल 233 पन्नों का है। यह दोनों ही भाषाओं में हाथों से लिखी हुई है ओर इसके लिए कोई टाइपिंग या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया है। आज भी देश भर से आने वाले लोगों के लिए संविधान की यह प्रति मुख्य आकर्षण का केंद्र है।

दुनिया भर से आने वाले विदेशी मेहमानों को भी यह मूल प्रति दिखाई देती है। संसद की लाइब्रेरी में संविधान की मूल कापी को रखा गया है। मूल प्रति को पहले 'फलालेन' के कपड़े में लपेटकर एक 'नेफ्थलीन बाक्स' में रखा गया है। संविधान 'मिलबोर्न लोन पेपर' पर लिखा गया है और साल 1994 में अमेरिका की तरह भारत ने भी संविधान की मूल प्रति को गैस कक्ष में रखने का फैसला लिया था।

इसके लिए भारत ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और अमेरिका के गेट्टी इंस्टीट्यूट के बीच करार किया गया था और इसी तरह का एक गैस कक्ष तैयार किया गया था। संसद भवन के पुस्तकालय में वैज्ञानिक विधि से तैयार गैस कक्ष में संविधान को सुरक्षित रखा गया है। इस स्ट्रांग रूम में आर्द्रता 40- 50 के बीच होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त आक्सीजन का स्तर दो से अधिक फीसद तक होना चाहिए। इसकी प्रमुख वजह यह है कि भारतीय संविधान को काली स्याही से लिखा गया है। स्याही आसानी से उड़ जाती है यानी आक्सीडाइज हो जाती है। इसे बचाने के लिए उमस (आर्द्रता) की मात्रा 50 ग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रखने की जरूरत होती है।

अब केवल तीन जिले ही वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित

जनसत्ता विशेष

लोकसभा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सुरक्षा बलों ने 2019 से अब तक 29 शीर्ष नक्सलियों को मार गिराया और अकेले इस साल माओवादियों की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के 14 सदस्य मारे गए हैं। राय ने कहा कि अब केवल तीन जिले ही वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित हैं। मंत्री ने दावा किया कि वामपंथी उग्रवाद मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 2014 के 10 से घटकर 2025 (अक्तूबर तक) पांच रह गई है, जो 50 फीसद की कमी है। उन्होंने कहा कि वहीं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी इस अवधि के दौरान 91 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई और यह संख्या 126 से घटकर 11 रह गई। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 के 126 से घटकर अक्तूबर 2025 में मात्र 11 रह गई। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के परिणाम को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा में 2010 के उच्चतम स्तर से 2024 तक 81 फीसद की भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रश्नकाल के दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि देश में 1967 से वामपंथी उग्रवाद है। इस वजह से एक समय होता था, जब पशुपतिनाथ से तिरूपति नाथ तक के पूरे हिस्से को लाल गलियारे कहा जाता था, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है। अब यह केवल कुछ ही क्षेत्रों तक समिति रह गया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले मार्च 2026 तक सरकार उग्रवाद से मुक्त कर देगी। इस मामले में केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने तालमेल बनाकर काम किया है, लेकिन अब से पूर्व की सरकारों में यह सीधे राज्य का मामला माना जाता था।

इस सरकार में केंद्र सरकार ने इस पर एक व्यापक नीति बनाई है और नीति के तहत ही उग्रवाद को कम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए सभी राज्यों को सीएपीएफ की बटालियन दी गई है और इस समय वर्तमान में 574 बटालियन तैनात हैं। इन राज्यों में सक्रियता को बढ़ाने के लिए 815 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 17573 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और 10561 मोबाइल टावर की मदद से मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया गया है। नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार की ओर से की गई पहल के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 2014 के 10 से घटकर 2025 (अक्तूबर तक) पांच रह गई है, जो 50 फीसद की कमी है। उन्होंने कहा कि वहीं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी इस अवधि के दौरान 91 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई और यह संख्या 126 से घटकर 11 रह गई।

मंत्री ने दावा किया कि आने वाले मार्च 2026 तक सरकार उग्रवाद से मुक्त कर देगी। इस मामले में केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने तालमेल बनाकर काम किया है, लेकिन अब से पूर्व की सरकारों में यह सीधे राज्य का मामला माना जाता था।

भारत और स्वीडन मिलकर कम करेंगे कार्बन उत्सर्जन

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

टाटा स्टील जैसी अग्रणी भारतीय कंपनियों ने घरेलू इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सात परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वीडिश प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों के साथ हाथ मिलाया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जैसे-जैसे भारत 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, देश के बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक विकास एवं दीर्घकालिक जलवायु महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए इन कठिन क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करना आवश्यक होगा।

भारत दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का सात फीसद तक उत्पन्न करता है। वहीं, चीन 30 फीसद और अमेकिा 14 फीसद कार्बन उर्त्सजन करता है। भारत में कार्बन उर्त्सजन का प्रमुख कारण कोयले पर अधिक निर्भरता का होना है। हालांकि, भारत इसे कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं में इस्पात निर्माण के लिए रोटरी भट्टों में हाइड्रोजन का उपयोग, हरित सीमेंट के उत्पादन के लिए 'स्टील स्लैग' का पुनर्चक्रण तथा सीमेंट के कार्बन मुक्त होने में सहायता के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) का उपयोग शामिल है।

इसमें कहा गया कि प्रमुख आइटी उद्योग परिवर्तन साझेदारी के तहत भारत में 'प्री-पायलट' (शुरुआती परीक्षण) व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सात नवीन परियोजनाओं का चयन किया गया है। इन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वीडिश ऊर्जा एजंसी से वित्त पोषण प्राप्त होगा।

अग्रणी भारतीय एवं वैश्विक कंपनियां, अनुसंधान संस्थान तथा प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक भारत के इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों के लिए इन सात कार्बन मुक्त (डीकार्बोनाइजेशन) परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमुख प्रतिभागियों में टाटा स्टील, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, जिंदल स्टील, प्रिज्म जानसन, सेमविजन के साथ-साथ स्वीडिश प्रौद्योगिकी अग्रणी कंथल तथा स्वेरिम शामिल हैं। बयान में कहा गया कि भारत के शीर्ष संस्थान आइआइटी बाम्बे, आइआइटी-आइएसएम धनबाद, आइआइटी भुवनेश्वर, आइआइटी हैदराबाद और दत्ता मेघे कालेज आफ इंजीनियरिंग इन सात परियोजनाओं में भागीदार हैं।

भारत दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का सात फीसद तक उत्पन्न करता है। वहीं, चीन 30 फीसद और अमेकिा 14 फीसद कार्बन उर्त्सजन करता है। भारत में कार्बन उर्त्सजन का प्रमुख कारण कोयले पर अधिक निर्भरता का होना है। हालांकि, भारत इसे कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।

पेरिस करार में है तापमान कम करने का संकल्प

2015 में हुए पेरिस समझौते में लगभग एक दशक की बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पहले दिन नेताओं ने धरती के प्रदूषण (कार्बन उत्सर्जन) को कम करने के उद्देश्य से पेरिस समझौते के एक प्रमुख घटक, अनुच्छेद 6 के विवरण को अंतिम रूप दिया। यह अनुच्छेद कार्बन क्रेडिट की प्रणाली के माध्यम से जलवायु प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 देशों को उत्सर्जन में कमी का व्यापार करने की अनुमति देता है, जिससे उच्च प्रदूषक कम प्रदूषक राष्ट्रों से कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।

खुदरा भागीदारी बढ़ने से पड़ेगा असर | रपट | इसका श्रेय दीर्घकालिक निवेश को दिया जा सकता है

म्यूचुअल फंड का आकार 2035 तक 300 लाख करोड़ रुपए होगा

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

म्यूचुअल फंड योजनाओं के तहत प्रबंधन-अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) वर्ष 2035 तक 300 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाने का अनुमान है जबकि इसी अवधि में प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरधारिता 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है।

सलाहकार फर्म बेन एंड कंपनी और निवेश मंच ग्रो की एक संयुक्त रपट कहती है कि एयूएम में उच्च वृद्धि खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और व्यापक डिजिटल पहुंच से प्रेरित है। 'हाउ इंडिया इन्वेस्ट्स' शीर्षक वाली रपट के मुताबिक, अगले दशक में भारतीय परिवारों में म्यूचुअल फंड की पहुंच 10 फीसद से बढ़कर 20 फीसद हो जाने की उम्मीद है। इसके मुताबिक, म्यूचुअल फंड उद्योग में वृद्धि की अगली लहर 'घरेलू स्वीकृति में वृद्धि, मजबूत डिजिटल सक्षमता, सहायक विनियमन और बढ़ते निवेशक विश्वास' से प्रेरित होगी।

सलाहकार फर्म बेन एंड कंपनी और निवेश मंच ग्रो की एक संयुक्त रपट कहती है कि एयूएम में उच्च वृद्धि खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और व्यापक डिजिटल पहुंच से प्रेरित है। 'हाउ इंडिया इन्वेस्ट्स' शीर्षक वाली रपट के मुताबिक, अगले दशक में भारतीय परिवारों में म्यूचुअल फंड की पहुंच 10 फीसद से बढ़कर 20 फीसद हो जाने की उम्मीद है। इसके मुताबिक, म्यूचुअल फंड उद्योग में वृद्धि की अगली लहर 'घरेलू स्वीकृति में वृद्धि, मजबूत डिजिटल सक्षमता, सहायक विनियमन और बढ़ते निवेशक विश्वास' से प्रेरित होगी। दूसरी ओर, इक्विटी हिस्सेदारी में अपेक्षित वृद्धि का श्रेय सट्टेबाजी आधारित कारोबार की जगह दीर्घकालिक निवेश की ओर बदलाव को दिया जा सकता है।

दूसरी ओर, इक्विटी हिस्सेदारी में अपेक्षित वृद्धि का श्रेय सट्टेबाजी आधारित कारोबार की जगह दीर्घकालिक निवेश की ओर बदलाव को दिया जा सकता है। साथ ही डिजिटल रूप से संचालित पैठ और मजबूत बाजार प्रदर्शन की भी इसमें भूमिका है। बेन इंडिया के साझेदार और वित्तीय सेवा प्रमुख सौरभ त्रेहान ने कहा, 'भारतीय परिवार पारंपरिक बचत की मानसिकता से धीरे-धीरे अधिक निवेश-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड एवं प्रत्यक्ष शेयर हाल के वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाले परिसंपत्ति वर्ग के रूप में उभरे हैं।' निवेश मंच ग्रो के सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हर्ष जैन ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा, 'हम भारतीयों में एक संरचनात्मक बदलाव देख रहे हैं।

अब वे 'पहले बचत' के बजाय 'पहले निवेश' की मानसिकता की ओर बढ़ रहे हैं।' रपट में भारत की 10,000 अरब अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में खुदरा निवेश को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में रेखांकित किया गया है। इसके मुताबिक, इस तरह के निवेश से वित्तीय परिवेश और व्यवसायों में सात लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे और वृद्धि पूंजी तक पहुंच आसान होगी।

विदेश मंत्री रुबियो ने समूह को लेकर प्रतिबद्धता जताई, कहा

भारत के साथ मिलकर क्वाड को और मजबूत करेंगे

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 9 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका 'क्वाड' के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा आने वाले वर्षों में इस समूह को और मजबूत करेगा। रुबियो ने सोमवार को कहा कि हम क्वाड के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में जापान और भारत के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने के लिए और काम करेंगे।

'क्वाड' (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया का एक समूह है। आस्ट्रेलिया-अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ताओं से पहले उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स तथा आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय में संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही।

कहा, विदेश मंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम यहीं इसी कमरे में क्वाड के साथ हुआ था।

रुबियो के अनुसार, इस साल जनवरी में विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर मुहर लगी, मैंने नीचे शपथ ली और सीधे इसी लिफ्ट से ऊपर आकर इस कमरे में पहुंचा। विदेश मंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम यहीं इसी कमरे में क्वाड के साथ हुआ था। रुबियो ने कहा कि जहां तक मुझे याद है, इस साल हमारी कम से कम तीन बैठकें हुई हैं। हम आने वाले साल में इस सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे तथा ऐसी और बैठकों की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, रुबियो और वोंग ने 21 जनवरी को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मुलाकात की थी।

शाहरुख खान न्यूयार्क टाइम्स की सबसे 'आकर्षक' लोगों की सूची में

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (भाषा)।

बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने न्यूयार्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के 67 सबसे आकर्षक लोगों की सूची में जगह बनाई है। अन्य मशहूर हस्तियों में सबरीना कारपेंटर, डोएची, विवियन विल्सन, निकोल शेर्ज़िगिंर, वाल्टन गोगिंस, जेनिफर लारेंस और कोल एस्कोला शामिल हैं।

शाहरुख को इस साल की शुरुआत में 'मेट गाला' में उनकी आकर्षक उपस्थिति के लिए यह पहचान मिली, जहां उन्होंने प्रसिद्ध डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया परिधान पहना था। सूची में शामिल दिग्गज अभिनेता के बारे में लिखा गया है कि अपने बेशुमार प्रशंसकों में शाहरुख के नाम से मशहूर, बालीवुड के सबसे बड़े स्टार और दुनिया के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक

सूची में सबरीना कारपेंटर, डोएची, विवियन विल्सन, निकोल शेर्ज़िगिंर, वाल्टन गोगिंस, जेनिफर लारेंस व कोल एस्कोला शामिल हैं।

शाहरुख मेट गाला में पहली बार मेहमान बनकर आए, जहां उन्होंने सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया परिधान पहना।

सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जर्मनी से मिली हार | हाकी | कांस्य पदक के लिए अर्जेंटीना से मुकाबला आज

नौ साल बाद पदक जीतने के इरादे से उतरेगा भारत

चेन्नई, 9 दिसंबर (भाषा)।

जर्मनी के हाथों करारी हार के साथ खिताब का सपना टूटने के बाद भारतीय टीम जूनियर हाकी विश्व कप के कांस्य पदक के मुकाबले के लिए बुधवार को अर्जेंटीना के खिलाफ उतरेगी तो नौ साल बाद पदक जीतने के लिए उसे दबाव में गलतियां करने की आदत से पार पाना होगा। पिछले दो विश्व कप में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम को उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो उसने सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन जर्मनी के खिलाफ की और उन्हें 1-5 से पराजय झेलनी पड़ी।

भुवनेश्वर में 2021 में और कुआलालंपुर में 2023 में हुए जूनियर विश्व कप में भारत क्रमशः फ्रांस और स्पेन से 3-1 से हारकर चौथे स्थान पर रहा था। होबर्ट में 2001 के बाद भारत ने दूसरा और आखिरी खिताब 2016 में लखनऊ में जीता था। तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके भारतीय टीम के मुख्य कोच पी आर श्रीजेश को बखूबी पता है कि यह पदक उनकी टीम के लिए कितना जरूरी है लेकिन उन्हें यह भी अहसास है कि सेमीफाइनल में स्पेन के खिलाफ आखिरी मिनटों में गोल गंवाकर 1-2 से हारी अर्जेंटीना की चुनौती को कमतर नहीं आंका जा सकता।

भारत ने होबर्ट में 2001 के बाद भारत ने दूसरा और आखिरी खिताब 2016 में लखनऊ में जीता था। तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके भारतीय टीम के मुख्य कोच पी आर श्रीजेश को बखूबी पता है कि यह पदक उनकी टीम के लिए कितना जरूरी है लेकिन उन्हें यह भी अहसास है कि अर्जेंटीना की चुनौती को कमतर नहीं आंका जा सकता।

दो बार की चैंपियन अर्जेंटीना ने 2021 में फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर खिताब जीता था। राउंड राबिन चरण में शानदार फार्म में रही भारतीय टीम ने 29 गोल किए थे और एक भी गोल गंवाया नहीं था लिहाजा गोलकीपर और डिफेंस को कोई चुनौती नहीं मिल सकी थी। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ 45 मिनट तक एक गोल से पिछड़ने के बाद तीन मिनट के भीतर कप्तान रोहित और शारदानंद तिवारी के गोलों के दम पर भारत ने बढ़त बना ली लेकिन आखिरी सीटी बजने से एक मिनट बाकी रहते गोल गंवाकर मैच को पेनल्टी शूटआउट में जाने दिया। शूटआउट में भारत ने जीत दर्ज की लेकिन मैच निर्धारित समय के भीतर ही खत्म हो सकता था। इसके बाद जर्मनी के सामने तो डिफेंस पूरी तरह चरमरा गया। पूरे मैच में भारत को एकमात्र पेनल्टी कार्नर मिला जबकि जर्मन टीम ने 'वन टच' यूरोपीय हाकी खेलकर दबाव बनाए रखा ।

Source:- दैनिक जागरण

इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई, उड़ानों में 10% कटौती

एयरलाइन हर हफ्ते पूर्व घोषित करीब 1,500 उड़ानों का नहीं कर सकेगी संचालन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को इंडिगो एयरलाइन को अपनी उड़ान समय-सारणी में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया। यह निर्णय उड़ान संबंधी नए रोस्टर नियम यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) लागू होने के बाद इंडिगो की हजारों उड़ानें के रद होने के कारण लिया गया है। नए सुरक्षा नियम लागू होने के बाद इंडिगो के परिचालन में गंभीर अव्यवस्था पैदा हुई है। परिणामस्वरूप सप्ताहभर में 4,000 से अधिक उड़ानें निरस्त की गईं और सैकड़ों फ्लाइटें देरी से रवाना हुईं। यात्री हलकान है और हवाई अड्डों पर अफरातफरी का माहौल है। मंगलवार को भी इंडिगो ने छह बड़े हवाई अड्डों से 422 उड़ानें रद कीं। उल्लेखनीय है कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह फैसला इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स की नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के साथ मुलाकात के बाद लिया। एल्बर्स को मंत्रालय ने समन किया था। इस बीच, इंडिगो प्रबंधन ने बताया कि छह दिसंबर तक के यात्रियों के पूरे पैसे रिफंड किए जा चुके हैं। 750 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि यात्रियों के खातों में पहुंच चुकी है।

संकट अभी भी बरकरार

- नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की इंडिगो के सीईओ के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया फैसला
- मंगलवार को भी इंडिगो ने छह बड़े हवाई अड्डों से 422 उड़ानें रद कीं, आठ दिन में 4,000 से अधिक उड़ानें रद
- इंडिगो ने कहा- रिफंड के तौर पर 750 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम यात्रियों के खातों में पहुंच चुकी

उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स बैठक की। आइएएनएस

बड़ा सवाल : इंडिगो की फ्लाइटें रद होने पर उसकी जगह कौन एयरलाइन देगी सेवा

सरकार के स्तर पर सख्ती दिखाने के बावजूद सवाल यह है कि क्या देश की दूसरी एयरलाइनें इंडिगो की जगह लेने को तैयार हैं। एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी कंपनियां खुद जूझ रही हैं। एअर इंडिया पर विस्तार का बोझ है तो स्पाइसजेट के पास सितंबर 2025 तक सिर्फ 19 सक्रिय विमान हैं जबकि अकासा पायलटों और रखरखाव की कमी से परेशान है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना तैयारी के इतनी उड़ानों को दूसरी कंपनियों को स्थानांतरित किए जाने से किराया बढ़ने का खतरा है। एअर इंडिया एक्सप्रेस का विंटर शेड्यूल ग्रीष्म काल के मुकाबले छह प्रतिशत कम है। अकासा ने पहले ही 5.7 प्रतिशत और स्पाइसजेट ने 26 प्रतिशत बढ़ोतरी की है।

देश के विमानन उद्योग में विमानों के साथ ही पायलटों की कमी गंभीर समस्या

भारत के विमानन उद्योग में विमानों के साथ ही पायलटों की कमी गंभीर समस्या है। जून 2025 तक 694 विमान संचालन में थे, जोकि साल के अंत तक 800 से ऊपर पहुंच चुके हैं। विमानन कंपनियां जो नए विमान ले रही हैं वह नैरोबाडी वाले हैं। हर नए विमान के लिए 10-15 पायलट की जरूरत होती है। तत्काल 1,500-2,100 पायलटों की भर्ती को जरूरी बताया जा रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, फ्लाइटों में कटौती आपरेशन को स्थिर करने और रद्दीकरण रोकने के लिए जरूरी है। कटौती मुख्य रूप से उन रूटों में की गई हैं जहां सबसे ज्यादा मांग और जो सबसे ज्यादा व्यस्तता रहती हैं। जहां इंडिगो अकेली उड़ान भरती है, वहां प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच, इंडिगो ने मंगलवार को दावा किया है कि उड़ानों की स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो रही है। सरकार ने भी माना है कि स्थिति तेजी से सुधरी है लेकिन डीजीसीए को इस बात का भरोसा नहीं है कि देश की सबसे बड़ी यह विमानन कंपनी सर्दियों के व्यस्त मौसम में अपने वादे के मुताबिक उड़ानें संचालित कर सकेगी। लिहाजा नियामक ने विंटर सीजन (मार्च, 2026 तक) की सूची से इंडिगो की उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है।

सोमवार देर शाम डीजीसीए ने एक नोटिस जारी कर विंटर सीजन के दौरान इंडिगो की उड़ानों में पांच प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी। इसे बढ़ाकर मंगलवार को 10 प्रतिशत करने का मतलब हुआ कि इस सीजन में इंडिगो हर हफ्ते तकरीबन 1,500 उड़ानें पूर्व घोषणा के मुताबिक नहीं चला सकेगी। इस बार सर्दियों में इंडिगो की तरफ से हर हफ्ते 15,014 उड़ानों की तैयारी की थी।

उड्डयन मंत्री नायडू ने एक्स पर लिखा-' इंडिगो के आंतरिक क्रू रोस्टरिंग, शेड्यूल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन में खामियों से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। जांच जारी है और जरूरी कार्रवाई होगी। हम इंडिगो के कुल रूट्स को 10% कम करने का आदेश दे रहे हैं।' मंत्रालय का मानना है कि इससे एयरलाइन का परिचालन स्थिर होगा और उड़ानों के रद होने की संख्या में काफी कमी आएगी। यह कटौती का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि इस कटौती का पालन करते हुए भी इंडिगो अपने सभी गंतव्यों पर पहले की तरह उड़ानें जारी रखेगी। लेकिन इसकी कटौती की भरपाई कौन सी एयरलाइंस करेगी, यह अभी सवाल है।

(पेज-5 भी देखें)

2036 तक हर सात में एक भारतीय होगा वरिष्ठ नागरिक

नई दिल्ली, एएनआइ: देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और 2036 तक बुजुर्गों की संख्या 22.74 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसके चलते स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल सुविधाओं का उपयोग जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं।

कांग्रेस सांसद सीके कुमार रेड्डी के सवाल पर लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने की उम्मीद है। इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है यानी हर 7 में एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक होगा। वहीं, 2036 तक अनुमानित जनसंख्या 153 करोड़ होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अव्यय योजना': गृह राज्य मंत्री ने बताया कि वृद्धों की आबादी में तेज बढ़ोतरी स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां खड़ी करेगी। इन उभरती चिंताओं के मद्देनजर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक अप्रैल, 2021 से अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) लागू की है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सीय देखभाल और मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद भी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय-अधिकारिता मंत्री करते हैं। इस परिषद में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों पर सलाह देते हैं।

सरकार का अनुमान

10.16 करोड़
लोग थे 2011 में 60 साल से ऊपर

22.74 करोड़
लोग होंगे 60 साल से ऊपर 2036 में

हॅंगे बुजुर्ग 2050 तक कुल आबादी में नीति आयोग का अनुमान

2050 तह हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग

साल 2023 में नीति आयोग ने बताया था कि दुनियाभर में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी जन्मदर गिरने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की वजह से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। आयोग ने अनुमान व्यक्त किया था कि 2050 तक कुल जनसंख्या के 19.5 प्रतिशत बुजुर्ग होंगे, जो फिलहाल 10 प्रतिशत हैं। अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा।

बिहार में तीन नए विभाग और दो निदेशालयों के गठन पर मुहर

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

नीतीश कुमार। फाइल

बिहार में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभागों और दो निदेशालयों के गठन की स्वीकृति दी गई है। युवाओं को नौकरी और रोजगार देने तथा कुशल बनाने के लिए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाया गया है। वहीं अब तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को समाहित कर उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। अभी तक मंत्रिमंडल विभाग के अंतर्गत चल रहे सिविल विमानन निदेशालय को अलग कर सिविल विमानन विभाग बनाया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए विभागों के गठन के साथ तीन मौजूदा विभागों के नाम भी बदले गए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा। श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया है।

एयरलाइन चाहे कितनी बड़ी हो, यात्रियों को परेशान नहीं कर सकेगी : नायडू

- इंडिगो की वजह से घरेलू हवाई सेवाओं के प्रभावित होने का मामला लगातार दूसरे दिन संसद में उठा
- नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया, कहा- सख्त कार्रवाई की जाएगी
- इंडिगो के सीईओ ने यात्रियों से फिर माफी मांगी, कहा- अब हमारा परिचालन पूरी तरह स्थिर हो गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इंडिगो एयरलाइन की वजह से घरेलू हवाई उड़ान सेवाओं के प्रभावित होने का मामला लगातार दूसरे दिन संसद में उठा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि चाहे कोई एयरलाइन कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे नियमों की अनदेखी करने या उसकी प्लानिंग की असफलता की वजह से यात्रियों को किसी सूरत में परेशान नहीं करने दिया जाएग। नायडू ने इस पूरे विवाद के लिए फिर से इंडिगो को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो के सीईओ एल्बर्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने समन भी किया था जिसके बाद वह मंगलवार को नायडू से मिलने पहुंचे। वहां भी नायडू ने उन्हें यही संदेश दिया कि जो हुआ उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यात्रियों के सभी पैसे, बैगेज आदि लौटाने संबंधी मंत्रालय के निर्देश का पालन करने को कहा।

राममोहन नायडू। फाइल

इंडिगो ने मंगलवार को दावा किया कि एयरलाइन अब पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और उसके आपरेशंस अब स्थिर हो गए हैं। साथ ही एयरलाइन हर प्रभावित यात्री की जरूरतों को पूरा करने में जुटी हुई है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को जारी अपने नए वीडियो संदेश में एक बार फिर यात्रियें से उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। एल्बर्स ने अपने संदेश में कहा- 'पहले हमने अनुमान लगाय था कि 10-15 दिसंबर तक सब सामान्य हो जाएगा लेकिन अब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आज यानी नौ दिसंबर को ही हमारा परिचालन पूरी तरह स्थिर हो गया है। वेबसाइट पर दिख रही सभी फ्लाइट्स तय समय के साथ उड़ान भर रही हैं हालांकि कुछ मार्गों में अभी समायोजन किया जाना बाकी है।' उन्होंने यह भी बताया है कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं या विलंब हुआ है, उन्हें रिफंड देने की प्रक्रिया जारी है और यह रोजाना आधार पर हो रहा है।

एल्बर्स ने बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता यह थी कि जितने भी यात्री एयरपोर्ट पर फंसे थे, उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य या घर पहुंचाया जाए। उसके बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू की गईं। लाखों यात्रियें को पूरा रिफंड मिल चुका है। सामान भी यात्रियों के घर पहुंचा दिय गया है, बाकी बचे सामान को भी बहुत जल्द डिलीवर कर दिया जाएगा। हम हर यात्री की हर जरूरत को पूरा करने में जुटे हैं। नेटवर्क बहाली के बारे में उन्होंने बताया कि विगत पांच दिसंबर को सिर्फ 700 फ्लाइट्स उड़ा पाए थे, छह दिसंबर को 1,500, सात दिसंबर को 1,650 और सोमवार और मंगलवार को 1,800 से ज्यादा। इंडिगो सीईओ का उक्त बयान आने से पहले मंगलवार को दोनों सदनों में इंडिगो की तरफ से हवाई सेवाओं के रद करने का मुद्दा विपक्षी दलों ने बताया।

स्पाइस जेट एयरलाइंस के निदेशक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

जागं, सिवान : बिहार के सिवान में जिला उपभोक्ता फोरम ने आठ वर्ष पूर्व स्पाइस जेट एयरलाइंस पर रिफंड मामले में बड़ा फैसला किया है। फोरम ने मई, 2025 में यात्री को टिकट रिफंड का पूरा पैसा सूद समेत वापस करने का निर्देश दिया था, इसका अनुपालन नहीं होने पर मंगलवार को स्पाइस जेट एयरलाइंस के निदेशक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

भारत में अमेरिका और चीन के मुकाबले कम हवाई जहाज

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली : भारत में हवाई जहाज से चलने वाले यात्रियों की संख्या दुनिया में सबसे तेज गति 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, लेकिन इस अनुपात में हवाई जहाज की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हवाई यात्रा के मामले में भारत वैश्विक रूप से दुनिया का तीसरा सबसे बाजार बन गया है, पर उस हिसाब से भारत में हवाई जहाज की संख्या नहीं है। हवाई यात्रा के मामले में भारत से आगे अमेरिका व चीन है जहां यात्री हवाई जहाजों की संख्या क्रमशः 8,000 और 7,300 है। भारत में यह संख्या सिर्फ 810 है। भारत में घरेलू व विदेशी दोनों मिलाकर 30 करोड़ से अधिक यात्री हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। चीन में सालाना 70 करोड़ से अधिक यात्री हवाई यात्रा करते हैं जो भारत के मुकाबले दोगुना से अधिक है, लेकिन चीन में हवाई जहाज की संख्या भारत के मुकाबले आठ गुना से अधिक है। अमेरिका में सालाना 90 करोड़ यात्री हवाई यात्रा करते हैं।

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथारिटी (आइएटीए) के मुताबिक हवाई जहाज की कमी वैश्विक स्तर पर है और अगले पांच साल से पहले इसमें सुधार होने की उम्मीद भी नहीं है। कोरोनाकाल के दौरान हवाई जहाज का निर्माण प्रभावित हुआ जिसे मांग के मुताबिक अब तक नहीं लाया जा सका है। आइएटीए के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 16,004 हवाई जहाज की जरूरत है और निर्माता कंपनियों को इसके आर्डर भी मिल चुके हैं, लेकिन निर्माता कंपनियां सालाना सिर्फ 10,720 हवाई जहाज का ही उत्पादन कर पा रही है। मांग व आपूर्ति में सालाना 5,284 यूनिट का अंतर है। 17,000 से अधिक का बैकलाग है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में सीमित कंपनियां यात्री हवाई जहाज का निर्माण करती हैं। मुख्य रूप से दो कंपनियां ही हवाई जहाज का निर्माण करती है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने भी नए विमान की खरीदारी का आर्डर दे रखा है और अगले पांच साल में भारतीय हवाई जहाजों की संख्या 1,400 से अधिक हो जाएगी।

- **भारत में हवाई यात्रियों की संख्या दुनिया में सबसे तेज 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही**
- **उत्पादन सीमित होने से वैश्विक स्तर पर हवाई जहाजों की भारी कमी**

हवाई यात्रा की कीमतों पर अंकुश का कोई नियम नहीं

सरकार के मुताबिक हवाई जहाज में यात्रा से जुड़े टिकट की कीमतों पर अंकुश लगाने का कोई नियम नही है। टिकट का मूल्य पूरी तरह से मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। हालांकि समय-समय पर जरूरत के मुताबिक सरकार टिकट मूल्य की सीमा तय करती है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। कोरोना काल में सरकार ने हवाई जहाज के टिकट के मूल्य पर सीमा लगाई थी। वैश्विक स्तर पर भी हवाई जहाज के टिकट का मूल्य मांग व आपूर्ति के सिद्धांत से तय होता है।

सौर तूफान अध्ययन में भारत के आदित्य-एल1 ने की मदद

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 ने सौर तूफान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे विज्ञानियों को यह समझने में मदद मिली कि मई 2024 में आए सौर तूफान से पृथ्वी पर इतनी असामान्य घटनाएं क्यों हुई थीं? यह पिछले दो दशक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान है। यह भारत की वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आदित्य एल1 को सितंबर 2023 में लांच किया गया था। आदित्य-एल1 की मदद से भारत अब शक्तिशाली सौर तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को कहा कि आदित्य-एल1 ने नासा के विंड सहित छह अमेरिकी उपग्रहों के साथ मिलकर काम किया और चुंबकीय क्षेत्र को सटीकता से मापा। इससे शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष में कई सुविधाजनक प्वाइंट या जगहों से एक साथ इस दुर्लभ घटना का

आदित्य-एल 1 की मदद से शोधकर्ता अंतरिक्ष में कई प्वाइंट से कर सके एक ही सौर तूफान का अध्ययन

भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में नेतृत्व क्षमता को किया प्रदर्शित, सौर तूफान के बारे में बढ़ी समझ

अध्ययन करने में मदद की।

इसरो के मुताबिक 2024 में आए सौर तूफान को 'गैनन तूफान' के नाम से जाना जाता है। उसने पृथ्वी के पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सूर्य पर विशाल विस्फोटों की श्रृंखला जिन्हें 'कोरोनल मास इजेक्शन' (सीएमई) कहा जाता है के कारण यह तूफान आया था। सीएमई सूर्य से अंतरिक्ष की ओर उठने वाले गर्म गैस और चुंबकीय ऊर्जा के विशाल बुलबुले होते हैं। जब ये पृथ्वी से टकराते हैं तो हमारे उपग्रहों, संचार प्रणालियों, जीपीएस और यहां तक कि बिजली ग्रिड के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। भारतीय विज्ञानियों की टीम ने इस संबंध में 'एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' नामक पत्रिका में अहम शोध पत्र प्रकाशित किया है।

मई 2024 के सौर तूफान के दौरान, विज्ञानियों ने पाया कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, जो सौर तूफान के अंदर मुड़ी हुई रस्सियों की तरह होते हैं, तूफान के भीतर टूट रहे थे और फिर से जुड़ रहे थे।

इसलिए अलग तरह का था मई 2024 में आया सौर तूफान

आमतौर पर सीएमई मुड़ी हुई 'चुंबकीय रस्सी' की तरह होते हैं जो पृथ्वी के निकट आते ही धरती के चुंबकीय ढाल के साथ संपर्क बनाती है। इस बार, दो सीएमई अंतरिक्ष में टकराई और एक दूसरे को इतनी मजबूती से दबाया कि उनमें से एक के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं टूट गई और नए तरीके से फिर से जुड़ गई। इस प्रक्रिया को 'चुंबकीय पुनर्संयोजन' कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के इस अचानक बदलाव ने तूफान के प्रभाव को अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। पहली बार, शोधकर्ता अंतरिक्ष में कई सुविधाजनक बिंदुओं से एक ही चरम सौर तूफान का अध्ययन कर पाए। आदित्य-एल1 मिशन से प्राप्त सटीक चुंबकीय क्षेत्र मापों की बदौलत, विज्ञानी इस क्षेत्र का मानचित्रण करने में सक्षम हुए। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि वह क्षेत्र जहां सीएमई का चुंबकीय क्षेत्र टूट रहा था और फिर से जुड़ रहा था, वह विशाल था। यह खगोलीय घटना लगभग 13 लाख किमी क्षेत्र में यानी पृथ्वी के आकार के लगभग 100 गुना क्षेत्र में हो रही थी।

शेख हसीना ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार बताया

नई दिल्ली, आइएएनएस : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की प्रशंसा की। उन्होंने संकट के समय उन्हें शरण देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

एक खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि वह बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को कैसे देखती हैं, तो हसीना ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और दोनों देश के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की कद्र करती हूं। व्यक्तिगत और कूटनीतिक स्तर पर खतरे के समय मुझे दी गई शरण के लिए आभारी हूं। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बांग्लादेश के हित में हैं और वे स्थायी क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद

बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने संकटकाल में समर्थन के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं निजी बातचीत और रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहती। हालांकि, मैं भारत के लोगों की लगातार मदद के लिए उनकी आभारी हूं। पिछले साल अगस्त में जब हसीना की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार हिंसक प्रदर्शन के बीच गिर गई, तब वह भारत आ गईं। हाल ही में ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। आरोप था कि हसीना प्रशासन द्वारा छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ को मिल रही धमकियों को बताया गंभीर स्थिति

राज्य के सहयोग न करने पर पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर लेने या केंद्रीय बल बुलाने का है अधिकार : आयोग

एसआइआर पर सुनवाई

आयोग से कहा, स्थिति से निपटें नहीं तो अराजकता फैल जाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल में विशेष मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बीएलओ को मिल रही धमकियों और राज्य सरकारों के कथित असहयोग पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर स्थिति बताया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह इस स्थिति से निबटे नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। यह भी कहा कि वह एसआइआर में बाधा या असहयोग की घटनाएं कोर्ट के संज्ञान में लाएं, कोर्ट उचित आदेश देगा। कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एसआइआर बिना किसी बाधा या खामियों के हो। हालांकि, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आयोग के पास व्यापक अधिकार हैं। राज्य सरकार को आयोग का सहयोग करना चाहिए और सुरक्षा देनी चाहिए।

सहयोग न करने की घटनाएं कोर्ट के संज्ञान में लाएं, कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती तो आयोग के पास स्थानीय पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि स्थिति फिर भी नहीं सुधरती तो केंद्रीय बलों को बुलाना होगा।

ये टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने बंगाल में एसआइआर के दौरान बीएलओ को मिल रही धमकियों का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सनातनी संसद संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में बंगाल में एसआइआर का अंतिम प्रकाशन होने तक राज्य पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन करने की मांग है। वैकल्पिक मांग में एसआइआर के पूरी होने तक बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश मांगा गया है। संगठन की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील वी. गिरि ने कहा कि बंगाल में एसआइआर की ड्यूटी में लगे बीएलओ के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए वहां केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया जाए क्योंकि राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। गिरि ने कहा कि बीएलओ को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जस्टिस बाग्ची ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका में मात्र एक एफआइआर का जिक्र है। बाकी उल्लेख तो ऐतिहासिक संदर्भ हैं तो क्या एक एफआइआर के आधार पर कोई आदेश जारी किया जा सकता है। तभी चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग ने बंगाल सरकार को कड़ा पत्र लिखा है क्योंकि बीएलओ को धमकाने, उनके काम में बाधा डालने और राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के घेराव की घटनाएं सामने आई हैं।

कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग के कार्यालय का घेराव इसलिए किया गया, क्योंकि बीएलओ बहुत थक गए थे और आत्महत्या कर रहे थे। द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की राजनीतिक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। द्विवेदी ने कहा कि आयोग ऐसे माहौल में काम कर रहा है, जहां केरल, बंगाल और तमिलनाडु राज्य सरकारें एसआइआर चाहती ही नहीं हैं व विरोध कर रही हैं।

असम का मुद्दा उठा

वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने असम में एसआइआर न होने और सिर्फ मतदाता सूची पुनरीक्षण होने का मामला उठाते हुए कहा कि वहां सबसे ज्यादा घुसपैठिये हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका पर भी आयोग को नोटिस जारी किया। इसके अलावा उप्र व तमिलनाडु में एसआइआर से संबंधित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने लगातार नई याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दलों को लग रहा है कि इस मंच पर उनकी बात उठ सकती है। कोर्ट ने एसआइआर के राजनीतिकरण पर चिंता जताई।

वन्यजीव संरक्षण के लिए अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड

नई दिल्ली, वि.: वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनंत अंबानी को अमेरिका में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें वनतारा के जरिये जानवरों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया इस उपलब्धि के साथ अनंत अंबानी ने एक खास रिकार्ड भी बनाया है। वह इस सम्मान को पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले यह अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपतियों जान एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन सहित हालीवुड हस्तियों और कई वैश्विक नेताओं को दिया जा चुका है।

इस सम्मान के साथ एक बार फिर 'वनतारा' का काम दुनिया के सामने चर्चा में आ गया है। वनतारा आज दुनिया के सबसे अलग और बड़े वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट्स में शामिल है। यहां घायल, बीमार और संकट में पड़े जानवरों को नई जिंदगी देने के साथ-साथ विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने और उन्हें दोबारा सुरक्षित माहौल में लौटाने के लिए लगातार काम किया जाता है। अवार्ड लेते हुए अनंत अंबानी ने कहा कि यह सम्मान मुझे 'सर्वभूत हित' यानी सभी जीवों की भलाई के रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जानवर हमें जीवन में संतुलन और संवेदनशीलता सिखाते हैं।

प्रतिष्ठित अमेरिकी अवार्ड पाने वाले सबसे युवा व पहले एशियाई बने अनंत, वनतारा को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान करतीं सोसाइटी की अध्यक्ष डा. रोविन गैजर्ट। सौ. रिलायंस फाउंडेशन

देश को नीचा दिखातीं नियामक संस्थाएं

राजीव सचान

यदि नियामक संस्थाएं सक्षम नहीं बनीं तो निजी क्षेत्र की कंपनियां वैसी ही मनमानी कर सकती हैं, जैसी इंडिगो ने की

उड़ानों के रद होने से परेशान विमान यात्री। फाइल

बहुत दिन नहीं हुए जब विषाक्त कफ सीरप कोल्ड्रिफ के मामले में यह सामने आया था कि नियामक संस्थाओं ने अपना काम सही तरह नहीं किया। इस विषाक्त कफ सीरप के सेवन के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। देश में दवा निर्माण के लिए नियामक संस्था-केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ नियम तय करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देने, दवा निर्माण इकाइयों के निरीक्षण और दवाओं के नमूनों का परीक्षण किए जाने जैसे काम राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण करते हैं। राज्यों के ऐसे प्राधिकरणों की क्षमताएं अलग-अलग हैं और सीएसडीएओ के पास ऐसे अधिकार नहीं कि वह राज्यों के प्राधिकरणों के कामकाज की निगरानी रख सके। विषाक्त कफ सीरप से 25 बच्चों की मौतों के बाद ऐसी खबरें आईं कि दवा निर्माण एवं उनके परीक्षण की व्यवस्था को और सक्षम बनाया जाएगा, लेकिन कहना कठिन है कि ऐसा हो सकेगा और उसके नतीजे में कोल्ड्रिफ जैसे मामले फिर सामने नहीं आएंगे। कायदे से दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता की जांच-परख करने वाली संस्थाओं को सक्षम बनाने का बीड़ा तभी उठा लिया जाना चाहिए था, जब कुछ वर्ष पहले गांबिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी कफ सीरप के सेवन से इन देशों के कई बच्चे मर गए थे।

अपने देश में हर क्षेत्र के लिए नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या वे पर्याप्त सक्षम हैं और अपना काम सही तरीके से कर पा रही हैं? ताजा मामला विमानन सेवाओं की नियामक संस्था डीजीसीए का है। इंडिगो एयरलाइन ने डीजीसीए के बनाए नियमों को लागू करने के स्थान पर उनकी अनदेखी करने का फैसला किया और वह भी तब, जब अन्य एयरलाइंस के साथ उसे भी इसके लिए करीब दो वर्ष का समय मिला था। अन्य एयरलाइंस ने तो डीजीसीए की ओर से पायलटों को आराम के घंटे बढ़ाने संबंधी नियमों पर अमल कर लिया, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और वह भी तब जब अन्य एयरलाइंस घाटे में चल रही हैं और इंडिगो मुनाफे में। इंडिगो ने नए नियमों को मानने के बजाय ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि डीजीसीए को अपने नियमों पर अमल को टालना पड़ा। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई, क्योंकि इंडिगो ने बड़ी संख्या में अपनी उड़ानों को रद किया। इसके चलते लाखों यात्री परेशान हुए। उनके समय के साथ धन की तो बर्बादी हुई ही, उनके जरूरी काम भी अटक गए। किसी की परीक्षा छूटी तो किसी का इंटरव्यू या फिर जरूरी मीटिंग अथवा अन्य कोई काम। लाखों विमान यात्रियों को जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई, उसका आकलन करना कठिन है।

इंडिगो ने अपनी उड़ानें रद कर विमान यात्रा को पंगु कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि डीजीसीए को उसके समक्ष घुटने टेकने पड़े। उसने विमानन बाजार में अपनी हिस्सेदारी का लाभ उठाकर डीजीसीए को जिस तरह झुकने के लिए बाध्य किया, उससे इस नियामक संस्था के साथ सरकार की भी किरकिरी हुई, क्योंकि डीजीसीए के झुकने का मतलब है भारत सरकार का झुकना। मोदी सरकार को यह आभास होना चाहिए कि इंडिगो प्रकरण से मजबूत सरकार की उसकी छवि को धक्का लगा है। लाखों विमान यात्रियों के सामने जो संकट पैदा हुआ, उससे देश की भी बदनामी हुई, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों के रद होने से देश के साथ विदेश के यात्री भी परेशान हुए। यह खेद की बात है कि डीजीसीए में से किसी ने इसकी सुधि नहीं ली कि इंडिगो उसकी ओर से तय किए गए नियमों का पालन करने की दिशा में कुछ कर रही है या नहीं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि डीजीसीए में कोई यह देखने वाला नहीं था कि यदि विमानन बाजार में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो उसकी ओर से तय किए गए नियम लागू नहीं करेगी तो अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग को तो गलत संदेश जाएगा ही, जिन कंपनियों ने उसके नियमों का पालन किया, वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगी।

एक ऐसे समय जब निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस भूमिका का और विस्तार होना तय है, तब नियामक संस्थाओं का सक्षम होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अभी कुछ ही नियामक संस्थाएं ऐसी हैं, जिन्हें सक्षम और सजग कहा जा सकता है। ज्यादातर नियामक संस्थाएं कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। कोई पर्याप्त अधिकारों से लैस नहीं है तो कोई संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है। विभिन्न क्षेत्रों से रह-रहकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो यह बताते हैं कि नियामक संस्थाएं किसी गड़बड़ी या मनमानी को रोकने में नाकाम ही अधिक रहती हैं। यदि नियामक संस्थाएं सक्षम नहीं बनीं तो निजी क्षेत्र की कंपनियां वैसी ही मनमानी कर सकती हैं, जैसी इंडिगो ने की। सरकार को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यदि नियामक संस्थाएं प्रभावी नहीं बनीं तो निजी क्षेत्र की कंपनियां बेलगाम होंगी और इसके नतीजे में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता गिरेगी। नियामक संस्थाओं को केवल इसलिए ही प्रभावी नहीं बनना होगा, ताकि उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुधरे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर सही ढंग से समाधान हो। उन्हें इसलिए भी प्रभावी बनना होगा, क्योंकि कोई देश अपनी संस्थाओं की सजगता से ही सबल और विकसित बनता है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

आजकल

विश्व का कायाकल्प करती एआइ

असल में तीन साल पहले जब चैटजीपीटी को दुनिया के सामने पेश किया गया था तब पहली बार करोड़ों आम लोग एआइ को इस्तेमाल करते हुए यह महसूस कर पाए कि यह तकनीक इंसानों की तरह सोच सकती है, लिख सकती है, कोड बना सकती है और मनचाहा कुछ भी रच सकती है। अब एआइ का जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है और कोई भी तिकड़म उसे वापस बोतल में नहीं डाल पाएगी–भले ही इसके असंख्य खतरे क्यों न हों। कोई भी देश अब इस तकनीक में पिछड़ना नहीं चाहता है

जन जीवन का हिस्सा बनती एआइ। प्रतीकात्मक

ायब्र हो रही हैं। ग्राहक सेवा में, 2025 ह पहला साल है, जब फार्च्यून 500 ंपनियों के आधे से ज्यादा उपभोक्ता टरैक्शन पूरी तरह एआइ एजेंट्स भालने लगे हैं। इस मामले में दावा कि ये एआइ एजेंट 120 भाषाओं में ाराप्रवाह तरीके से और तकरीबन र्णता की सांस्कृतिक समझ के साथ ये ाषाएं बोल सकते हैं। खतरा मौलिकता र टिके रचनात्मक उद्योगों के लिए भी । चित्रकारी, वीडियोग्राफी, संगीत और फल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों को एआइ ी ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। शहूर कान फेस्टिवल में एआइ-निर्मित ार्ट फिल्म (द क्रो) का जूरी पुरस्कारों रनर-अप) में चुना जाना और ग्रैमी वाइर्स में "सर्वश्रेष्ठ गीत जिसमें एआइ ा महत्वपूर्ण योगदान हो"- नामक नई टेगरी का शुरू किया जाना इसकी स्टीक करता है कि अब कोई उद्योग आइ के असर से बच नहीं सकता है।

इससे सबसे ज्यादा फायदा उद्योग लाने वालों को और सबसे ज्यादा ातरा उन्हीं उद्योगों में काम करने वाले र्मचारियों को है। तकनीक के सहारे त्पादकता बढ़ने वाले जिस चमत्कार ा वादा किया गया था, वह अब हमारे मने साक्षात मौजूद है, लेकिन इसका क क्रूर चेहरा भी है, जो कई नौकरियों े खात्मे की शक्ल में दिख रहा है। त्पादकता और रोजगार के आंकड़ों की ार-संभाल करने वाली एजेंसी- मैकिंजी ा अनुमान है कि 2023 से अब तक नरेटिव एआइ ने वैश्विक जीडीपी में .4 ट्रिलियन डालर जोड़े हैं। यानी जर्मनी ी जितनी अर्थव्यवस्था है, उतना फायदा आइ की वजह से दुनिया को मिल चुका , लेकिन यह फायदा बेहद संकुचित हिस्से में कैद है। एआइ टूल्स और माडलों के मालिक, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के दिग्गज और वे उच्च-कुशल कर्मचारी जो एआइ के बल पर अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं-इससे बेशुमार ढंग से लाभान्वित हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, एआइ के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नौ प्रतिशत नौकरियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। 2030 तक 18 प्रतिशत और नौकरियों के लिए "ऊंचा जोखिम" है। सबसे तेज झटका सफेद कालर वाले पेशों, जूनियर अकाउंटेंट, कापीराइटर, अनुवादक, यहां तक कि रेडियोलाजिस्ट जैसे तमाम पेशों से जुड़े कर्मचारियों को लगने वाला है। पत्रकारिता, डिजाइनिंग, कोडिंग, मिडिल लेवल के मैनेजर- ऐसी नौकरियों पर असली खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ट्रक ड्राइवरों जैसे पेशों के लिए फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन यदि एआइ से चलने वाली कारों का दौर आगे बढ़ा तो ऐसी नौकरियों से भी लोग बाहर किए जा सकते हैं।

एआइ की वजह से हुआ सबसे गंभीर बदलाव संभवतः भू-राजनीतिक है। एआइ के दौर में डाटा नया तेल है और इसकी रिफाइनरियां दो देशों के पास हैं। अमेरिका और चीन मिलकर इसका अधिकांश हिस्सा नियंत्रित कर रहे हैं। हालांकि यूरोपीय देश भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी भूमिका मैदान से बाहर खड़े दर्शक जैसी है। कहने को तो भारत और सऊदी अरब आदि देश भी इसमें हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बनने की उनकी क्षमताओं को लेकर कई संदेह हैं। हालांकि भारत के पक्ष में जो बात जाती है, वह एआइ के लिए काबिल इंजीनियरों की फौज मुहैया कराने के मामले में है। यानी जनसांख्यिकी लाभ के आधार पर भारत पूरी दुनिया के लिए टैलेंट की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है, लेकिन इसका वह पूरा फायदा नहीं उठा पाता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश वीजा और तमाम कायदे गिनाकर भारतीय प्रतिभाओं का रास्ता रोकने की भरसक कोशिश करते हैं। एआइ के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं का दोहन आज भी औद्योगिक क्रांति के दौरान दिए गए फार्मूले के तहत होता है, जिसके मूल में सस्ते मजदूरों को काम के बदले चंद टुकड़े दिए जाते थे। असंतुलन का यह परिदृश्य खुद विकसित देशों में भी है। ओपनएआइ, माइक्रोसाफ्ट, गूगल डीपमाइंड, मेटा एआइ, एनवीडिया जैसी चंद कंपनियां ही एआइ पर एकाधिकार कायम की हुई हैं। नई कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है।

नए खतरों की आहट : फर्जी खबरें, डीपफेक से तैयार फोटो-वीडियो सच्चाई को झुठला रहे हैं। सच क्या है- इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है। वजह यह है कि एक गढ़े हुए झूठ को दूसरे झूठ से काटने की कोशिश होती है और हमें इसका पता ही नहीं चलता। एआइ की मदद से स्वायत्त (खुद चलने का फैसला करने वाले) हथियारों का निर्माण चोरीछिपे चल रहा है और दावा है कि कुछ सेनाएं ऐसे स्वचालित हथियारों की तैनाती तक कर चुकी हैं, जिन्हें दागने के लिए किसी इंसान या उनके निर्देशों की जरूरत तक नहीं है। एआइ से जुड़ी हस्तियां और कंपनियां मानने लगी हैं कि अगले दशक तक दुनिया में ऐसी सुपरइंटेलिजेंट (अत्यधिक बुद्धिमान) मशीनें अस्तित्व में आ सकती हैं, जिन्हें इंसान नियंत्रित ही न कर पाएं।

मानवता के हित में हो तकनीकी का इस्तेमाल

जेन एआइ के तीन साल बाद हम जिस स्थान पर खड़े हैं, वहां से तीन मुख्य रास्ते निकलते दिखते हैं। पहला यह है कि तकनीक में एकाधिकार हासिल करने की कोशिशों के बरक्स भारत जैसे देश चुनौती दें। प्रतिभा और जनसांख्यिकी के बल पर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी पूंजी, माहौल और बड़े स्तर पर तैयारियों की जरूरत है। मुश्किल यह है कि सेमीकंडक्टर (माइक्रोचिप्स), जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट- एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर जो कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों के लिए थ्रीडी ग्राफिक्स और छवियों को तेजी से बनाता है जिससे मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे काम आसान हो जाते हैं) के मामले में अमेरिका-चीन जैसे देशों को काफी बढ़त हासिल है और इनकी बराबरी पर आने में ही दशक भर से ज्यादा समय लग सकता है। दूसरा रास्ता यूरोपीय देश सुझा रहे हैं। कड़े कानूनों, पारदर्शी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संधियों को अपनाकर एआइ के इस्तेमाल को मानवता के हित के लिए केंद्रित किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने से एआइ की प्रगति धीमी पड़ने का संकट है, लेकिन इससे तकनीक का विश्वव्यापी वितरण न्यायसंगत हो जाता है। तीसरा, एआइ को मुफ्त में चलने वाले ओपन सोर्स माडलों में केंद्रित किया जा सकता है। इससे पूरी दुनिया का हर शख्स विश्वस्तरीय एआइ टूल्स का इस्तेमाल कर कुछ नया बना सकता है। इससे हालांकि नवाचार और रचनात्मकता का विस्फोट हो सकता है, लेकिन कई किस्म की अराजकता भी फैल सकती है और एआइ से बने स्वचालित हथियारों की होड़ अनियंत्रित हो सकती है। कहना मुश्किल है कि आने वाले वक्त में दुनिया इनमें से कौन सा रास्ता चुनती है। हो सकता है कि अगले तीन-चार वर्षों में इसकी कोई साफ तस्वीर सामने आए, लेकिन यह तय है कि इसका फैसला मशीनें, तकनीक या किसी कोड से नहीं, बल्कि राजनैतिक दूरदर्शिता, नैतिकता और साहस से होगा।

चैटजीपीटी ने हमें जो सबक दिया, वह यह है कि तकनीक अपने आप में न अच्छी होती है, न बुरी। वह वही होती है जो हम उसे बनाने का फैसला करते हैं। तीन साल पहले हमने एक दरवाजा खोला था। अब सवाल यह नहीं है कि हम उसे बंद कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि हम उसके पार जो दुनिया बनाएंगे, उसमें इंसान की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और उसकी साझी सच्चाई बची रहेगी या नहीं।

-अभिषेक कुमार सिंह

प्रश्न – AI ने वैश्विक कार्य प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित किया है? इनके प्रयोग से प्रर्यावरण व राजगार संबंधित उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाले।

38 Marks

मंथन

नए भारत के निर्माण का मंत्र

राष्ट्र तभी प्रगति करेगा जब सरकार, समाज और नागरिक तीनों मिलकर सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ेंगे

आचार्य राघवेंद्र पी. तिवारी
कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

सामुदायिक जलवायु-प्रबंधन को समर्थन देता 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान। फाइल

हाल में उडुपी स्थित श्रीकृष्ण मठ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिपादित नौ व्रत अथवा नौ मंत्र केवल नीतिगत घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति का खाका हैं। ये मंत्र भारत के समकालीन परिवर्तन को वैचारिक दिशा देते हैं, जिसके केंद्र में नागरिक-सशक्तीकरण, समावेशी एवं सतत विकास और राष्ट्र-हित की व्यापक अवधारणाएं निहित हैं। इनका समन्वित प्रभाव ऐसे भारत के निर्माण की संभावनाओं को सुदृढ़ करता है, जो आत्मविश्वासी, आधुनिक, सर्वसमावेशी हो, साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हो। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित नीतियां भारत को वैश्विक नेतृत्व के पथ पर अग्रसर करने के साथ ही नागरिकों में जिम्मेदारी, कर्तव्यबोध और राष्ट्र-निर्माण की चेतना जागृत करती हैं।

पीएम मोदी ने नागरिकों से जल संरक्षण और नदियों की सुरक्षा करने की अपील की है, ताकि देश की जल संपत्ति सुरक्षित रह सके। जल संरक्षण का यह आह्वान जल जीवन मिशन और भूजल प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ जुड़कर जल उपयोग नीति को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन आज का सबसे बड़ा संकट है, और इसका स्थायी समाधान प्रकृति-केंद्रित जीवनशैली है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से वे पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने पर बल देते हैं। पौधारोपण राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रतिबद्धताओं और सामुदायिक जलवायु-प्रबंधन को समर्थन देता है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर बल देना देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और आत्मनिर्भर भारत के औद्योगिक ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग से स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है एवं देश का धन बाहर जाना रुकता है।

भारतीय दर्शन कहता है कि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, ये चारों परस्पर पूरक इकाइयां हैं। अर्थात व्यक्ति न तो राष्ट्र से अलग है, न राष्ट्र व्यक्ति से। इस अवधारणा को मूर्तरूप देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति से कम से कम एक गरीब के जीवन को सुधारने का संकल्प लेने की बात कह कर पीएम मोदी समावेशी विकास की भावना को मजबूती प्रदान करते हैं, एवं दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की अवधारणा का विकेंद्रीकरण करते हैं।

प्राकृतिक खेती का प्रोत्साहन रासायनिक खाद आधरित कृषि से हटकर पुनर्योजी एवं टिकाऊ कृषि का मार्ग प्रशस्त करता है, जो स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जलवायु सहनशीलता तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रगति आवश्यक है, किंतु प्रकृति का संतुलन बिगाड़कर नहीं। मोटे अनाज आधारित स्वस्थ जीवनशैली पोषण सुरक्षा और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। योग को दैनिक जीवन में शामिल करना मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस हेतु उनका आह्वान स्वास्थ्य प्रणाली में निवारक दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करता है और भारत को वैश्विक सांस्कृतिक पूंजी को सशक्त बनाता है। पांडुलिपि संरक्षण नीति ज्ञान-संरक्षण और सांस्कृतिक अनुसंधान को नई दिशा देती है। कम से कम पच्चीस धरोहर स्थलों का भ्रमण करने का मंत्र सांस्कृतिक साक्षरता, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही भारत की संस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर देता है।

वर्तमान के तेजी से बदलते संस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भों में ये सूत्र भारत को स्थिरता, नवाचार, समावेशिता और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाले स्तंभ सिद्ध होंगे। यह नौ-सूत्रीय दृष्टि न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि भविष्य के भारत की मजबूत नींव भी रखती है। परंपरा और प्रगति, स्थानीय और वैश्विक, नवाचार और जीवन मूल्य, एक साथ मिलकर राष्ट्र को नए शिखर पर ले जाएंगे। समष्टि रूप में ये मंत्र नागरिक-केंद्रित राष्ट्रनिर्माण की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जहां व्यक्तिगत आचरण और सार्वजनिक नीति परस्पर पूरक बनकर सतत, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से समन्वित भारत के निर्माण को संभव बनाते हैं। ये मंत्र आधुनिक भारत के सर्वांगीण परिवर्तन, नैतिक शक्ति, सामूहिक संकल्प और वैश्विक उत्तरदायित्व की दिशा को स्पष्ट करते हैं। इनका सार है कि राष्ट्र तभी प्रगति करेगा जब सरकार, समाज और नागरिक तीनों मिलकर सामूहिक संकल्प से आगे बढ़ेंगे। आइये हम सभी इनको अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाएं।

भारत में 17.5 अरब डालर का निवेश करेगी माइक्रोसाफ्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद दिग्गज आइटी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने किया एलान

न्यूयार्क, रायटर: दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसाफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में 23 अरब डालर का नया निवेश करेगी। इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा यानी 17.5 अरब डालर भारत में निवेश किया जाएगा, क्योंकि कंपनी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह एशिया के किसी देश में किया जाने वाला सबसे ज्यादा निवेश होगा। खास बात यह है कि कंपनी ने यह एलान सीईओ सत्य नडेला की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुलाकात के बाद की।

नई दिल्ली में पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला

पीएम मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''जब एआइ की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर सकारात्मक है। सत्य नडेला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह जगह है जहां माइक्रोसाफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इस मौके का इस्तेमाल नवाचार करने और एक बेहतर धरती के लिए एआइ की ताकत का फायदा उठाने के लिए करेंगे।'' एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में नडेला ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेरणादायक बातचीत के लिए धन्यवाद। देश की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी 17.5 अरब डालर का निवेश करने जा रही है। यह एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा।' कंपनी ने कहा कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा और दूसरे शहरों में उसके 22,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो माइक्रोसाफ्ट के कारोबार की विविधता को दिखाते हैं। इससे पहले मंगलवार को दिन में ही माइक्रोसाफ्ट ने कनाड़ा में 5.42 अरब डालर के निवेश का एलान किया था। माइक्रोसाफ्ट के वर्तमान में कनाडा के 11 शहरों में 5,300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। पिछले महीने, माइक्रोसाफ्ट ने पुर्तगाल में एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10 अरब डालर और संयुक्त अरब अमीरात में 15 अरब डालर का निवेश करने का एलान किया था।

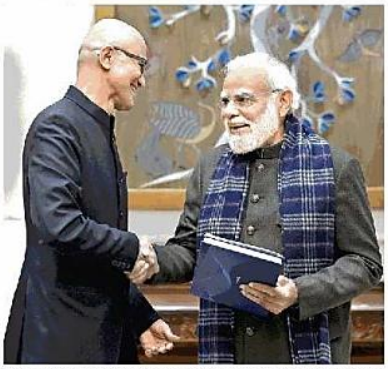

भारत सबसे तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मार्केट में से एक

भारत, इस समय दुनिया के सबसे तेजी से बढ रहे डिजिटल मार्केट में से एक है और यहां नए और बड़े मौकों की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश की सबसे बड़ी कंपनियां भी भारत में जमकर निवेश कर रही हैं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहा था कि जब पूरा विश्व अनिश्चितताओं से भरा है, ऐसे समय में भारत को एक अलग ही नजरिये से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब सुस्ती की बात होती है तो भारत विकास की कहानी लिखता है।

काग्निजेंट ने भी विस्तार के लिए प्रतिबद्धता जताई

माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के अलावा कई अन्य तकनीकी कंपनियों के सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मंगलवार को मिले। काग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार एस, इंटेल के सीईओ लिप बू टैन भी पीएम से मुलाकात की और भारत में निवेश और अपने संचालन के विस्तार का आश्वासन दिया। काग्निजेंट ने कहा कि उन्होंने पीएम को आश्वासन दिया कि कंपनी देश के उभरते शहरों में विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रोथ और कौशल विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगी।

यह एशिया के किसी भी देश में माइक्रोसाफ्ट द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश, देश में कंपनी के 22,000 कर्मचारी

देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में अगले वर्ष मई में

जागरण संवाददाता, वाराणसी

सार्वजनिक परिवहन के रूप में देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में अगले वर्ष मई में शुरू हो जाएगी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने मंगलवार को बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक की चार किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 16 मिनट का समय लगेगा। प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 50 या 100 रुपये रखने की योजना है। प्रत्येक गोंडोला (केबल कार) में लगभग 10 लोग बैठ सकेंगे। रोप कार सेवा में 148 गोंडोला रखने की योजना है। प्रतिदिन लगभग एक लाख लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। रोपवे परियोजना की लागत लगभग 800 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि पहले लगभग पांच हजार लोग प्रतिदिन श्रीकाशी विश्वनाथ धाम आते थे। आज यह संख्या लगभग दो लाख तक पहुंच गई है। ऐसे में रोपवे

वाराणसी : रोपवे परियोजना मई में शुरू करने की योजना है और इस समय गोंडोला का नियमित परीक्षण किया जा रहा है। जागरण

सुविधा शहर के आधुनिकीकरण की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर की तंग सड़कों और सघन आबादी के कारण मेट्रो रेल परियोजना व्यवहार्य नहीं थी, इसलिए रोपवे का निर्णय लिया गया। काशी में इस वर्ष लगभग सात करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जबकि 2024 में यह संख्या 6.5 करोड़ थी।

देश के पहले हाइड्रोजन जलयान को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल कल काशी में दिखाएंगे हरी झंडी

जागरण संवाददाता, रामनगर

- एक साल से चल रहा था परीक्षण, 50 यात्री कर सकेंगे यात्रा
- वाटर टैक्सी के रूप में चलेगा जलयान, किराया अभी तय नहीं

संचालन के लिए तैयार देश का पहला हाइड्रोजन चलित जलयान। जागरण

देश का पहला हाइड्रोजन चलित जलयान गुरुवार को काशी में जनता को समर्पित किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नमोघाट पर गुरुवार को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अंतरदेशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) इसे वाटर टैक्सी के रूप में अभी नमोघाट से रविदासघाट के मध्य चलाएगा।

मंत्रालय का दावा है कि यह जलयान देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान है। इसके संचालन से गंगा में इको-फ्रेंडली और प्रदूषण-मुक्त यात्रा की शुरुआत होगी।

इसका सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक नियमित परिचालन होगा। इसमें 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन के साथ पूरी तरह साउंड-लेस है। अभी किराया तय नहीं किया गया है। पूर्णतया स्वदेशी इस जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है। इसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है और भविष्य में इसे कैथी स्थित मार्कंडेय धाम तक संचालित करने की योजना है।

काशी में इसका संचालन शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड करेगा। बेंगलुरु की कंपनी हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगी। हाइड्रोजन चलित जलयान के लिए नमो घाट और असि घाट पर दो हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनका संचालन बेंगलुरु की कंपनी 'न्यू इंडिया हाइड्रोजन' करेगी। रविवार और सोमवार को रामनगर मल्टीमाडल टर्मिनल व रविदास घाट के बीच जलयान का परीक्षण किया गया। हालांकि, पिछले एक साल से जलयान को यहां कई तरह के परीक्षणों से गुजारा गया है।

आस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध

सिडनी, रायटर: आस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है। आस्ट्रेलिया में मंगलवार आधी रात से टिकटाक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित कई प्लेटफार्मों तक बच्चों की पहुंच को रोक दिया गया है।नए कानून के तहत दस सबसे बड़े प्लेटफार्म्स को बच्चों को ब्लाक करने या 3.3 करोड़ डालर तक के जुर्माने का सामना करने का आदेश दिया गया है।

इस कानून की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों ने आलोचना की है पर माता-पिता व बच्चों के अधिकारों के पैरोकारों ने इसका स्वागत किया है। बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को लेकर कई और देश भी ऐसे उपायों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

- **नए कानून के तहत, दस सबसे बड़े प्लेटफार्म्स को बच्चों को ब्लाक करने का आदेश**
- **प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, प्रतिबंध यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले**

आस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा,16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले। उन्होंने राज्यों व स्थानीय नेताओं को इंटनेट मीडिया प्रतिबंध पर उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा,यह वह सांस्कृतिक बदलाव है,जिसकी माता-पिता को ज्यादा मानसिक शांति देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है कि आस्ट्रेलियाई बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे। उन्होंने बच्चों से कहा, स्कूल की छुट्टियों का पूरा लाभ उठाएं। फोन पर समय बिताने के बजाय, कोई नया खेल शुरू करें, नया वाद्य यंत्र बजाना सीखें या वह किताब पढ़ें जो आपकी आलमारी में रखी है। सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों और परिवार के साथ आमने-सामने अच्छा समय बिताएं।

इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध से किशोर चिंतित : इन प्रतिबंधों से सबसे अधिक परेशान वे किशोर हैं, जिनका संपर्क पूरी तरह इंटरनेट मीडिया पर निर्भर था। दक्षिण आस्ट्रेलिया के आउटक बैक में रहने वाले 15 वर्षीय राइली ऐलन को चिंता है कि वह अपने दूर-दराज रहने वाले दोस्तों से कैसे जुड़ेगा। बुडिन्ना से करीब पांच किमी दूर उसका घर है और उसके कई मित्र 70 किलोमीटर दूर तक फैले इलाकों में रहते हैं। इंटरनेट मीडिया ही उनके बीच संवाद का एकमात्र साधन था।

कानून को अदालत में दी चुनौती : उधर, सिडनी के 15 वर्षीय नोहा जोन्स और मैसी नेलैंड ने इस कानून को अदालत में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह नियम देश के 26 लाख किशोरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करता है। वहीं, कुछ किशोर भी मानते हैं कि इंटरनेट मीडिया के एल्गोरिद्म उन्हें देर रात तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

कटक में जीत की 'हार्दिक' बधाई

- पहले टी-20 में 101 रन से जीता भारत
- पांड्या ने 28 गेंदों में ठोके नाबाद 59 रन

अर्धशतकीय पारी के दौरान शॉट लगाते हार्दिक पांड्या ● एपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: करीब ढाई महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे स्टार आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को कटक के बाराबटी स्टेडियम में आलराउंड का प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने पहले टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर 101 रन से जीत दर्ज की। हार्दिक ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेली और 28 गेंदों में अविजित 59 रन बनाए, जिससे भारत ने छह विकेट पर 175 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को टी-20 में उसके सबसे कम स्कोर 74 रन पर ढेर कर दिया। इसमें भी हार्दिक ने डेविड मिलर का अहम विकेट चटकाया। ये भारत को टी-20 में दक्षिण अफ्रीका पर दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से हराया था। हार्दिक को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

पांड्या ने जमाया रंग: दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी-20 सीरीज में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल पर सभी की निगाहें थीं क्योंकि ये दोनों ही चोट से उबर कर वापसी कर रहे थे। उपकप्तान गिल (4) तो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या पूरे रंग में दिखे। सितंबर में हुए एशिया कप में श्रीलंका के विरुद्ध सुपर 4 मैच में चोटिल हुए हार्दिक ने बेंगलुरु के सेंटर आफ एक्सीलेंस में रिहैब पूरा कर पिछले सप्ताह ही सैयद मुश्ताक ट्राफी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी। पंजाब के विरुद्ध मैदान में उतरते ही हार्दिक ने अपने बल्ले से धमाल किया था और 42 गेंद में 77 रन की अविजित पारी खेलकर बड़ौदा को जीत दिलाई थी। मंगलवार को भी हार्दिक उसी अंदाज में दिखे। 12वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने अगले ओवर में केशव महाराज के ओवर में दो छक्के जड़े। 16वें ओवर में हार्दिक ने 150 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे एनरिक नोर्त्जे को दो चौके लगाए और भारत की रनगति को बनाए रखा। उन्होंने 25 गेंदों में छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी में चार छक्के और छह चौके जड़े और भारत को संकट से निकाला।

शीर्षक्रम ने किया निराश: टास हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ही ओवर में गिल पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर में भारतीय टीम ने कप्तान सूर्य (12) का विकेट गंवा दिया। पावरप्ले में भारतीय टीम की हालत खराब थी और बोर्ड पर केवल 40 रन जुड़े थे। पावरप्ले के समाप्त होने के बाद ही अभिषेक शर्मा (17) आउट हो गए। तिलक ने पारी को कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी खराब शाट खेलकर आउट हो गए।

कप्तान सूर्य की खराब फार्म जारी: कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फार्म कटक में भी जारी रही और वह केवल 12 रन के स्कोर पर आउट हो गए। लुंगी नगिदी की स्लोअर पर बड़ा शाट खेलने के प्रयास में वह मिडआन पर मार्करैम को कैच थमा गए। पिछले 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सूर्य कुमार यादव का औसत 15.33 रहा है और वे पिछले 20 मैचों में कोई अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। स्ट्राइक रेट भी 2022 के 187 से घटकर 127 पर आ गया है।

गेंदबाजों ने बरपाया कहर: लाल मिट्टी की पिच पर भारतीय गेंदबाज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी रहे। दक्षिण अफ्रीका ने ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन यहां उसका कोई असर नहीं दिखा। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में क्विंटन डिकाक को रिलप में अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया और उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। पावरप्ले में टीम का शीर्षक्रम ढह गया था और मध्यक्रम को निपटाने में भारतीय गेंदबाजों ने देर नहीं लगाई। बुमराह ने डेवाल्ड ब्रेविस (22) का विकेट लेने के साथ ही टी-20 में अपना 100वां विकेट लिया और वह सभी प्रारूपों में विकेटों का शतक लगाने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए।

100 विकेट तीनों प्रारूपों में लिए बुमराह ने, वह ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले लसिथ मलिंगा, टिम साउदी, शाहीन अफरीदी व शाकिब हसन के बाद पांचवें गेंदबाज हैं

विकेट लेने के बाद गिल के साथ बुमराह ● एएफपी

स्कोर बोर्ड

टास: दक्षिण अफ्रीका (गेंदबाजी) — प्लेयर आफ द मैच: हार्दिक पांड्या

भारत: 175/6 (20)

	रन	गेंद	4/6
अभिषेक का. जेनसेन बो. सिपमाला	17	12	2/1
गिल का. जेनसेन बो. नगिदी	4	2	1/0
सूर्यकुमार का. मार्करैम बो. नगिदी	12	11	1/1
तिलक का. जेनसेन बो. नगिदी	26	32	2/1
अक्षर का. ब्रेवीस बो. सिपमाला	23	21	0/1
हार्दिक अविजित	59	28	6/4
शिवम बो. फरेरा	11	9	2/0
जितेश अविजित	10	5	0/1

अतिरिक्त: 13 (वा: 4, ला: 9), विकेट पतन: 1-5 (गिल, 0.3), 2-17 (सूर्यकुमार, 2.4), 3-48 (अभिषेक, 6.3), 14-78 (तिलक, 11.4), 5-104 (अक्षर, 13.6), 6-137 (शिवम, 17.1), गेंदबाजी: नगिदी 4-0-31-3, जेनसेन 4-0-23-0, सिपमाला 4-0-38-2, नोर्त्जे 4-0-41-0, महाराज 2-0-25-0, फरेरा 2-0-13-1

दक्षिण अफ्रीका: 74 (12.3 ओवर)

डिकाक का. अभिषेक बो. अर्शदीप	0	2	0/0
मार्करैम बो. अक्षर	14	14	1/1
स्टब्स का. जितेश बो. अर्शदीप	14	9	2/0
ब्रेविस का. सूर्य बो. बुमराह	22	14	3/1
मिलर का. जितेश बो. पांड्या	1	3	0/0
फरेरा का. जितेश बो. वरुण	5	7	1/0
जेनसेन बो. वरुण	12	12	0/2
महाराज का. जितेश बो. बुमराह	0	2	0/0
नोर्त्जे बो. अक्षर	1	3	0/0
सिपमाला का. अभिषेक बो. शिवम	2	5	0/0
नगिदी अविजित	2	4	0/0

अतिरिक्त: 1 (वा:1), विकेट पतन: 0-1 (डिकाक, 0.2), 2-16 (स्टब्स, 2.3), 3-40 (मार्करैम, 5.1), 4-45 (मिलर, 6.1), 5-50 (फरेरा, 7.2), 6-68 (जेनसेन, 9.5), 7-68 (ब्रेविस, 10.2), 8-70 (महाराज, 10.5), 9-72 (नोर्त्जे, 11.2)
गेंदबाजी: अर्शदीप 2-0-14-2, बुमराह 3-0-17-2, वरुण 3-1-19-2, अक्षर 2-0-7-2, हार्दिक 2-0-16-1, शिवम 0.3-0-1-1

टी-20 में द. अफ्रीका का न्यूनतम स्कोर

74	बनाम भारत	कटक	2025
87	बनाम भारत	राजकोट	2022
89	बनाम आस्ट्रेलिया	जोहानिसबर्ग	2020
95	बनाम भारत	जोहानिसबर्ग	2023
96	बनाम आस्ट्रेलिया	केपटाउन	2020
98	बनाम श्रीलंका	कोलंबो	2018

भारत के विरुद्ध न्यूनतम टी-20 स्कोर

57	यूएई	दुबई	2025
66	न्यूजीलैंड	अहमदाबाद	2023
70	आयरलैंड	डब्लिन	2018
74	द. अफ्रीका	कटक	2025
80	श्रलेड	कोलंबो	2012

बाएं हाथ से सिक्का उछालकर भी टास हारे सूर्यकुमार यादव

विशाखापत्तनम वनडे में केएल राहुल ने बाएं हाथ से सिक्का उछालकर टास जीता था और भारत को 20 वनडे से चला आ रहा टास हारने का क्रम टूटा था। पहले टी-20 मैच की पूर्व संध्या पर जब सूर्य से टास को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी बाएं हाथ से सिक्का उछालूंगा। हालांकि सूर्य हमेशा दाएं हाथ से सिक्का उछालते हैं, लेकिन कटक में ओस फैक्टर को देखते हुए वह भी टास जीतना चाहते थे। टास के समय सूर्य ने बाएं हाथ से सिक्का उछाल, लेकिन ये गिरा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करैम की पक्ष में। मार्करैम ने बिना झिझक के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया।

पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाते गौतम गंभीर, सूर्य कुमार व देविशा ● पेट

गंभीर-सूर्य ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन

पुरी, ओड़िशा: कटक में पहले टी-20 मुकाबले से पूर्व भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव मंगलवार को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। सूर्य के साथ पत्नी देविशा शेट्टी के साथ मंदिर पहुंचे थे। गंभीर के अलावा टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक, तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में प्रार्थना की और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। सेवक रवि प्रतिहार ने विशेष पूजा का आयोजन किया और भारतीय टीम की सीरीज में सफलता के लिए अनुष्ठानिक दीप जलाया। गौतम गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहले टेस्ट से पूर्व कोलकाता के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर और गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट से पहले मां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए थे।